(b) and (c) The production cost of each the items is covered by the respective selling price. However, taking the working cost into account, loss is incurred on postcards and inland letters, while postal envelopes (letters) have yielded profits during this period. There is no proposal at present, specifically to eliminate the losses on these items. However, Postal tariffs are reviewed from time to time and the last revision was effected in June 1990.

Techno-Economic clearance of Projects by Central Electricity Authority

*550. SHRI SUNDER SINGH BHANDARI: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) what is the number of schemes that have been techno-economically cleared by the Central Electricity Authority for installation of Gas based Thermal Power Projects in various States during the last three years;

(b) when were these schemes received for techno-economic appraisal and what was their estimate at the time of submission; when were they cleared and what was the estimated cost of each at the time of clearance; and

(c) what steps are being taken by Government to reduce the period between receipt and clearance of a project by the Central Electricity Authority?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER (SHRI KALP NATH RAI): (a) and (b) 17 scheme with a total capacity of 5762.5 MW have been techno-economically cleared by the Central Electricity Authority for installation of Gas-based Thermal Projects in various States during the last three years. The required details in respect of these schemes are given in the Annexure. [*See* Appendix CLXIV, Annexure No. 62]

(c) In order to ensure that examination of schemes is conducted expeditiously, the Central Electricity Authority has issued guidelines to all State Electricity Boards/Utilities, or preparation of Feasibility Reports. On receipt of a Feasibility Report, a preliminary security is made and the project authority is immediately requested to furnish the missing details. After the preliminary examination, simultaneous examination of the scheme is undertaken in respect of various aspects such as reasonableness of the cost estimates, suitability and adequacy of transmission system, justification of the project from power demand and supply angle, suitability of the location of the project, Environment and Forest clearance, etc., and the scheme is accorded techno-economic clearance as soon as the essential inputs/ clearances are tied up.

उत्तर प्रदेश में अनपारा परियोजना के लिए जापानी सहायता

*551. **श्री अनन्तराम जायसवाल** क्या **विद्युत** मंत्री 28 जुलाई, 1992 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 2044 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनपारा परियोजना की पारेषण लाइनों पर कितनी राशि खर्च होगी और उसमें जापानी सहायता की राशि कितनी होगी तथा उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड उस पर कितनी राशि खर्च करेगा ;

(ख) क्या केंद्रीय सरकार को जापानी सहायता के आबंटन के भुगतान के लिए उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है, यदि हाँ, तो कब और यदि नहीं, तो क्या केंद्रीय सरकार उत्तर प्रदेश सरकार बिजली बोर्ड से ऐसा अनुरोध करने को कहेगी ; और

(ग) क्या केंद्रीय सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश देगी कि वह पारेषण लाइनें बिछाने में जो कमियां रह गई हैं उन्हें दूर करें ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) अनपारा "ब" ताप विद्युत केन्द्र से संबद्ध पारेषण, प्रणाली, उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (उ.प्र.रा.बो.बो.) सातवीं योजना पारेषण कार्य (220 के.वी. तथा अधिक) जिसकी अनुमानित लागत (1207.12 करोड रुपए थी, का एक भाग थी। इसमें शामिल अनपारा पारेषण प्रणाली की, लागत 422.56 करोड रुपए थी। सहायता के संदर्भ में ओ.ई.सी.एफ., जापान तथा उ.प्र.रा.बि.बो. का हिस्सा निम्नानुसार है :—

—ओ.ई.सी.एफ. सहायता के माध्यम से किए जाने वाले पारेषण कार्यों की लागत	378.61 करोड़ रु०
—राज्य द्वारा पारेषण कार्यों की लागत	43.95 करोड रु०

दिसम्बर, 1989 में उ.प्र.रा.बि.बो द्वारा ओ.ई.सी.एफ. से संबंधित पारेषण कार्यों की लागत को ओ.ई.सी. एफ. विद्युत विभाग/के.वि.प्रा. के परामर्श से संशोधित करके 525.10 करोड़ रुपए कर दिया गया था। उक्त अनुमान के अनुसार वित्त पोषण संबंधी स्वरूप निम्नानुसार है :—

I. ओ.ई.सी.एफ. वित्त पोषण के अंतर्गत कार्यों की लागत

(1) ओ.ई.सीए.फ. द्वारा सम्भावित वित्तपोषण (विनिमय दर—6.5 येन=1 रूपये	412.79 करोड़ रुपए)
(2) करों तथा प्रशासनिक प्रभारों के संदर्भ में उ.प्र. रा.बि.बो. द्वारा वित्तपोषण की जाने वाली लागत	112.40 करोड़ रुपये
(3) अनपारा पारेषण से सम्बद्ध अन्य कार्य जो ओ. ई. सी. एफ. के अंतर्गत शामिल नहीं हैं	43.95 करोड़ रूपय

पूर्व नियोजित पारेषण प्रणाली से संबंधित कार्य काफी पिछड़ गया है। चूंकि ओ.ई.सी.एफ. से निधियां अभी आवश्यक नहीं हैं, अतः उ.प्र.रा.बि.बो. से निधियों को जारी किए जाने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। विलम्ब के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल है :—

उ.प्र.रा.वि.बो. के सामने निधियों संबंधी समस्यायें होना, अपारा-उन्नाव 765 कि.मी. लाइन के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति में विलम्ब होना और वनरोपण कार्य हेतु भूमि का निर्धारण न कर पाना।

उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को इन कार्यों में तेजी लाने को कहा गया है।

STD facilities in Bihar

*552. SHRI S' S. AHLUWALIA Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that number of towns and importan cities despite the fact that telephon facilities are existing therein fc quite a long period;

(b) if so, what are the reasor therefor;

(c) whether Government hav drawn any action plan for providin STD facilities in the State of Biha in the near future;

(d) if so, the details thereof; an

(e) by when Government propos to provide STD facilities throughou the State of Bihar?

THE MINISTER OF STATE C THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI RAJESH PILOT): (a No, Sir. Most of the important citi and towns are covered by STD facility.

(b) Question does not arise.

(c) Yes, Sir.

(d) 209 stations in Bihar have ST facility.